894/884

राष्ट्रीय सहारा पृष्ठ-12
01-07-2014

खेतों की मिट्टी की सेहत सुधार कर ही बढ़ सकेगी उपज

बजट पूर्व ज्ञापन

- मृदा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हों
- फसल के रखरखाव बेहतर हों
- भंडारण सुविधाएं बेहतर बनें
- कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा हों
- शीतगृहों का निर्माण हो
- सिंचाई की नई तकनीक लाएं

नई दिल्ली (भाषा)। खाद्य मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव के बीच कई प्रमुख कृषि विशेषज्ञों ने आगामी बजट में खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, जल संरक्षण और फसल कटाई के बाद होने वाले कृषि उपजों के नुकसान को कम करने के उपायों पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया है। इन विशेषज्ञों ने देश भर में मृदा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने तथा किसानों की आय सुरक्षा के उपाय किए जाने का भी सुझाव दिया है।

खाद्य मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव के बीच नरेन्द्र मोदी सरकार अपना पहला आम बजट 10 जुलाई को पेश करेगी। सरकार के समक्ष महंगाई, विशेषकर फल, सब्जियों की महंगाई पर काबू रखना बड़ी चुनौती बनी हुई है। मई में खुदरा मूल्य आधारित मुद्रास्फीति बढ़ कर 8.3 प्रतिशत थी जबकि उपभोक्ता मूल्य आधारित खाद्य मुद्रास्फीति 9.6 प्रतिशत रही।

प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने कहा, 'बेहतर फसल के लिए मृदा यानी किसान के खेत की मिट्टी का स्वस्थ्य होना जरूरी है और खाद्य सुरक्षा के लिए यह अहम है। इसके लिए हम देश के हर प्रखंड में मृदा स्वास्थ्य निगरानी एवं सुधार केंद्र स्थापित कर सकते हैं।' स्वामीनाथन ने कहा, 'फसल कटाई के बाद उसके बेहतर रखरखाव संबंधी ढांचागत सुविधा के अभाव में बड़ी मात्रा में कृषि उपज खराब होती है। देश में अति आधुनिक अनाज भंडारण ढांचा तैयार करना होगा। आय सुरक्षा मजबूत करने के बारे में दिए अपने सुझाव में स्वामीनाथन ने कहा, 'कृषि उत्पादों पर आधारित ज्यादा-से-ज्यादा गैर कृषि रोजगार पैदा कर यह किया जा सकता है।'

बेंगलुरू स्थित कृषि संस्थान के प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने कहा, 'भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या बुनियादी ढांचे की कमजोरी है। सिंचाई, बाजार तथा परिवहन संबंधी ढांचागत सुविधाओं की कमी से खेती-बाड़ी की लागत अधिक है।' कुमार ने कहा, 'बागवानी क्षेत्र में नुकसान 40 से 50 प्रतिशत है। इसका कारण फसल कटाई के बाद की रखरखाव व्यवस्था, बेहतर परिवहन सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज, गोदामों आदि की कमी है। बजट में इसे दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही दलहन उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।'

प्रमोद कुमार ने कहा, 'फल एवं सब्जियों के मामले में अगर हम केवल बर्बाद होने वाले फसल का दो तिहाई हिस्सा ही बचा लें तो कीमत काफी हद तक नीचे आ जाएगी और किसानों का मुनाफा भी बढ़ेगा।' सिंचाई के बारे में कुमार ने कहा कि करीब 60 प्रतिशत कृषि कार्य मानसून पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ सिंचाई का तरीका पुराना है जिसमें काफी मात्रा में पानी बर्बाद होता है। ऐसे में बजट में टपक सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, संरक्षित खेती जैसी जल बचाने वाली प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की जरूरत है जिससे दीर्घकाल में कृषि ज्यादा टिकाऊ होगा।

प्रख्यात अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री वाईके अलघ ने भी जल संरक्षण के साथ सिंचाई पर ध्यान देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने दलहन पैदावार बढ़ाने के साथ साथ कृषि विविधीकरण पर जोर दिया है।

सुनीता गुप्ता
1/7/14
पत्रिका एवं समाचार पत्र अनुभाग

प्रतिलिपि :-
1. निदेशक कार्यालय
2. संयुक्त निदेशक (प्रसार)
3. अधिष्ठाता/संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
4. प्रभारी पी-पी-आई
5. प्रभारी सू. एस. आई
6. प्रभारी कटैट